جناب ڈپٹی چئیرمین: پلیز کنکلوڈ ---(مداخلت)---

ڈاکٹر فوزیہ خان: سر، ہمارا انداتا کسان ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ انداتا آتم ہتیا کیوں کررہا ہے، 27 فیصد انداتاؤں نے سوسائیڈ کیا ہے۔ یہ آنکڑے NCRB کے ہیں۔ ---(مداخلت)--- سر، ہم یوا پاور، ویمین پاور کیسے بڑھائیں گے، ہم فارمرس کی پاور کیسے بڑھائیں گے؟

جناب ڈپٹی چئیرمین: یور ایلوٹیڈ اِز اوور---(مداخلت)--- اِٹ اِز آل ریڈی اوور ---(مداخلت)---

ڈاکٹر فوزیہ خان: سر، میں کنکلوڈ کررہی ہوں۔ سر، میں کنکلوژن میں اتنا ہی کہوں گی کہ ہم کو سب کا ساتھ، سب کا وِکا، سب کا وِشواس کے ساتھ سچ میں اس دیش کو رام راجیہ بنانا ہوگا۔

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Message from Lok Sabha; Secretary General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting on 6th February, 2024, passed the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024.

I lay a copy of the said Bill on the Table.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS - *Contd..*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. K. Laxman.

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. During her Address, she made it very clear that landmark legislations have taken place under the Modi Government. Not only that, the emphasis was laid on most of the development programmes and, more particularly, on the pilgrimage destinations and historical sites in India. Ram Temple in Ayodhya has become a reality. Modi*ji* always wanted agriculture to be made profit-oriented. He wants the youth of this country, who are educated and qualified, to enter into agriculture fields. So, in spite of all odds, Modi*ji* has given a lot of sops for encouraging agriculture. Under PM-Kisan Nidhi, farmers have been provided with Rs.2.8 lakh crores, so far benefiting 11.8 crore farmers of this country. Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, farmers received Rs.1.5 lakh crores in his tenure of ten years. Farmers have received Rs.18

lakh crore in the past decade as MSP for paddy and wheat, which is two-and-half times higher than the amount paid in ten years preceding 2014 during the UPA regime. Farmers producing oilseeds and pulses have received Rs.1.25 lakh crore as MSP. In ten years, Rs.11 lakh crore have been spent to provide affordable fertilizers to farmers. In Telangana, Ramagundam Fertilizers and Chemicals, which had been closed down during the Congress regime, has been resumed by spending not less than Rs.6,300 crore. It is not only serving the farmers of Telangana and Andhra Pradesh, but also the entire south Indian farmers, who are now getting the fertilizers at affordable prices, and more than 3,000 local youth have got employment from this. In spite of all these odds, Modiji's Government is working for the poor. He does not want any poor family, any poor person to be starved of food. So, 80 crore people are being given free ration. As far as the Green Revolution is concerned, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana has provided an outlay to the tune of Rs.20,000 crores. As a result, fish production has increased from 95 lakh metric tons to 175 lakh metric tons. Export in fisheries has doubled. The world's largest grain storage plan has been launched in the co-operative sector. As far as housing is concerned, under the Pradhan Mantri Awas Yojana, in urban and gramin, not less than four crore people have got pucca houses. This number is almost six times the population of Australia. You can imagine how it feels when a poor family's dream of getting a pucca house gets fulfilled. Now, in this recent Budget, two crore more houses have been announced. Then, Pradhan Mantri SVANidhi Scheme has been launched for the benefit of street vendors. Almost 77.56 lakh loans have been distributed to street vendors and an amount of Rs.10,250 crore has been spent on this. Then, 905 kilometres of metro rail network has also been created, which is now supposed to be the largest metro rail network in the world. So, along with development, *vikas* and *virasat* is being taken care of under Modiji's Government. As has been rightly mentioned in the President's Address, Viksit Bharat is being erected on four pillars, namely, youth power, woman power, farmers and the poor.

Apart from this, as far as the health sector is concerned, Ayushman Bharat Scheme has helped nearly 3.5 crore citizens. When Modiji speaks of *sabka saath, sabka vikas'* तो जब वे गरीब के लिए कोई भी योजना बनाते हैं, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। मगर दो दिन पहले ही हमारे विपक्ष के नेता जब सामाजिक न्याय के बारे में जिक्र कर रहे थे, I was surprised to hear and note, जिन्होंने शुरुआत से लेकर आज तक, नेहरू के जमाने के लेकर आज तक, राहुल गाँधी तक और बीच में राजीव गाँधी तक हमेशा ओबीसी समाज का विरोध किया, and they have * the OBCs, right from Nehruji. When Kaka Kalelkar Commission

* Expunged as ordered by the Chair.

was constituted for the upliftment and empowerment of the OBCs and there were some recommendations for the OBCs by this Commission, they did not even allow the same to be discussed in the Parliament. That was the approach of this Congress Government. This shows how much concern they had for the OBCs. Moreover, when Mandal Commission's report was placed in the Parliament, being an Opposition leader, Shri Rajiv Gandhi, opposed it tooth and nail. He said that अगर आरक्षण होना चाहिए, तो आर्थिक रूप से होना चाहिए, जाति के नाम पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, वरना इस देश का जाति के नाम पर बंटवारा होगा। यह कांग्रेस का रवैया था और आज राहुल गाँधी के मगरमच्छी आँसू बहते हैं, चुनाव आते समय वे ओबीसी बन जाते हैं, एससी बन जाते हैं, एसटी बन जाते हैं, कभी जनेऊधारी भी बन जाते हैं, इसलिए मंदिर भी आ जाते हैं, लोगों को जानकारी है कि आज उनको सामाजिक न्याय के बारे में बात करने का कोई नैतिक हक नहीं है। आपके दल ने अम्बेडकर का जो अपमान किया, आपके दल ने अम्बेडकर को चुनाव में हराया। अम्बेडकर के "भारत रत्न" का जो जिक्र किया, यह "भारत रत्न" जब दिया गया था, तब वी.पी. सिंह सरकार और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से दिया गया था। इतना ही नहीं, इस बीच मोदी सरकार ने हमारे अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए हुए नाई समाज के कर्पूरी ठाकुर जी को किस तरह से .. (**व्यवधान**)..

श्री नीरज डांगी (राजस्थान) : ये गलत कह रहे हैं।

श्री उपसभापति : नीरज डांगी जी, प्लीज़ बैठिए।

डा. के. लक्ष्मण : आप एक बार देख लीजिए, यह इतिहास है। 75 साल के अंदर कर्पूरी ठाकुर को पहली बार "भारत रत्न" दिया गया। इतना ही नहीं राजनीति के अलावा, इससे ऊपर उठकर, प्रणब मुखर्जी दा को भी मोदी सरकार में "भारत रत्न" दिया गया। यह बीजेपी का काम है। आप जो हमेशा सामाजिक न्याय के बारे में बात करते हैं, नेहरू जी के जमाने में, he had written letter to the CMs saying that again, there should not be reservation in the name of caste. That letter was written in the year 1961. आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, सीताराम केसरी जी के ओबीसी होने के नाते, उनका किस तरह से अपमान किया गया, यह पूरी दुनिया जानती है। देश भी जानता है कि सीताराम केसरी के ओबीसी होने की वजह से उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, आज मोदी जी की सरकार ने 75 साल में पहली बार ओबीसी समाज के 27 नेताओं को मंत्रिमंडल में भागीदार बनाकर ओबीसी समाज का मान-सम्मान और गौरव बढ़ाया है। आज पहली बार अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ओबीसी समाज के बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय पाठशालाओं, सैनिक स्कूलों में हर साल चार लाख बच्चों को मोदी जी ने सुविधा प्रदान की है। यह काँग्रेस लगभग 50 साल के लिए सरकार में थी, तो मैं इनसे सीधा पूछना चाहता हूँ कि ओबीसी के हित के लिए, ओबीसी के उत्थान के लिए आपका मन क्यों नहीं बना? इतना ही नहीं, नीट के माध्यम से होने वाली एमबीबीएस और एमडी की परीक्षा में भी पहली बार मोदी जी की सरकार के आरक्षण देने से आज लगभग हजारों की संख्या में ओबीसी बच्चे

एमबीबीएस और एमडी की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं, जो भी आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण हैं, उन्हें भी मोदी जी की सरकार ने पहली बार ईडब्ल्यूएस के तहत दस परसेंट आरक्षण दिया है, इसलिए जब हम सबका साथ, सबका विकास बोलते हैं, तब हम इसे करके भी दिखाते हैं। चाहे कोई एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इनके साथ-साथ सवर्ण को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा, जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, जब उसे संवैधानिक दर्जा देने की बात आई, जब मोदी जी ने 2017 में पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा था, तब उस बिल को इसी काँग्रेस पार्टी, वामपंथी और क्षेत्रीय दलों ने राज्य सभा में किस तरह से हराया था, इसे पूरी दुनिया जानती है। ओबीसी समाज पर आपका कभी ध्यान नहीं गया था, मगर 2018 में फिर लोक सभा और राज्य सभा में बिल पास होने की वजह से आज जो 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, उस पर ठीक ढंग से अमल किया जा रहा है। इसलिए आज मोदी जी की सरकार ओबीसीज़ के लिए बात करती है। इसके साथ ही, तेलंगाना में भी सरकार ने तय आरक्षण पर ठीक से अमल नहीं किया है। आप चुनाव आने पर गारंटी की बात करते हैं और चुनाव के बाद आज कर्णाटक, हिमाचल प्रदेश और बाकी प्रदेशों में देख रहे हैं कि आपकी गारंटी किस तरह से एक्सपायर हो गई है। सिर्फ चुनाव के लिए नारा दे रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद किस तरह से ठुकरा रहे हैं, इसे सभी लोग जानते हैं। मोदी की गारंटी के मायने हैं कि जो बोलते हैं, उसे वे करके दिखाते हैं, इसलिए मोदी जी हैं, तो मुमकिन है। ...(**समय की घंटी**)... मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। अब तीसरी बार भी मोदी जी की सरकार बनने वाली है और हम दुनिया में तीसरा आर्थिक मजबूत देश बनने वाले हैं, यह मोदी जी की गारंटी है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र) : सर, शायद मैं दिन की आखिरी वक्ता हूँ, तो आप कृपया थोड़ी generosity दिखाएं।

सर, माननीया राष्ट्रपति ने जब अपने अभिभाषण की शुरुआत की थी, तब उनकी सबसे पहली स्टेटमेंट यह थी कि "This is my first address in this New Parliament Building. This magnificent building has been constructed at the beginning of "Azadi ka Amrit Kaal". It also resonates with the resolve to respect our democratic and parliamentary traditions." यह खुशी की बात थी, पर दुख इस बात का था कि तीन मौके थे, जहाँ पर उन्हें as a constitutional head of the state शामिल किया जा सकता था, पर उन्हें शामिल होने नहीं दिया गया। आप देखिए, देश की नई पार्लियामेंट में घुसपैठिए तो घुस आए, पर हमारी राष्ट्रपति को आने का मौका नहीं मिला। ...(**व्यवधान**)...

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

सर, उन्होंने संविधान की बात की कि हम संविधान का 75वां साल मना रहे हैं, तो उससे मुझे याद आया कि महाराष्ट्र सरकार को जिस तरीके से बनाया गया था, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी। चूँकि यह संविधान के शेड्यूल 10 के दायरे में आता है, इसलिए मैं सिर्फ दो मिनट लूँगी। "The Governor's decision to call for a floor test on 28th June, 2022 was illegal." यह गवर्नर साहब का रोल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। "The communication of the

Governor dated 30th June, 2022 calling Mr. Eknath Shinde to take oath as the Chief Minister is unconstitutional and out to be set aside." चूँकि संविधान का 75वां साल है और हमारी राष्ट्रपति ने इसके बारे में बोला है, इसलिए मैं इस बारे में बताना चाह रही थी। मैंने पूरी स्पीच सुनी भी और पढ़ी भी। मैंने तीन बार हिंदी में भी पढ़ी और इंग्लिश में भी पढ़ी, पर कहीं भी दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। वे दो शब्द क्या थे - एक शब्द था employment और दूसरा शब्द महंगाई था। 2014 का जो स्लोगन था - बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार - वह बार-बार मेरे कानों में गूंज रहा था। हम 2024 में बैठे हैं। जिन्होंने महंगाई खत्म करने की बात कही थी, उन्होंने आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया कर दिया है। माननीय राष्ट्रपति का जो यह अभिभाषण था, यह सरकार से ही आता है। इसमें सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है और सरकार के जो भी मंत्रालय हैं, वे अपने इन्पुट्स बताते हैं। सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक किताब है, उनकी 51 कविताएं उसमें हैं, उनकी कविता के चार शब्द यहां बोलना चाहती हूं -

"आदमी की पहचान,
उसके धन या आसन से नहीं होती,
उसके मन से होती है।
मन की फकीरी पर
कुबेर की संपदा भी रोती है।"

जहां पर देश के लिए फकीरी हो और देश के जो चार स्तम्भ की बात कर रहे हैं, जिसका वादा 2014 में भी किया था, चाहे वह नारी शक्ति की बात हो, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। * सर, मैंने सारे अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स देख लिए हैं और मैं जो शब्द यूज़ करने वाली हूं, वे अनपार्लियामेंटरी नहीं हैं। * क्योंकि संविधान के तौर-तरीकों का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इस पर चर्चा कर लूं।

सर, राष्ट्रपति जी ने बताया कि income tax returns किस तरीके से बढ़े हैं। सवा तीन करोड़ से सवा आठ करोड़ तक बढ़ गए हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन रिटर्न्स बढ़े हैं, टैक्स नहीं बढ़ा है, जो टैक्सेबल इन्कम है, वह नहीं बढ़ी है। 2019 और 2020 में number of taxpayers drop हुए हैं। सिर्फ 6.23 per cent of India's population tax pay करती है। सिर्फ 3 लाख 20 हज़ार लोग 50 लाख की gross income की टैक्सेबल इन्कम में आते हैं। यह देश की सच्चाई है। 10 साल की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी के बारे में ही बोल रही हूं। सर, जब नारी शक्ति के बारे में बात हुई। पहली महिला ट्राइबल राष्ट्रपति हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन हुआ और महिलाओं को उनके अधिकार देने और उनके लिए रिज़र्वेशन की बात हुई, जो खैर immediately लागू होने वाला नहीं है, महिलाओं को 2029 का वायदा किया गया है। आप लाइन लगा लो, कतार में लग जाओ पर दरवाजे तो हम 2029 में ही खोलेंगे। उसमें भी अगर हम राष्ट्रपति जी को सुनते, तो हमारा दिल महिला होने के नाते, राजनीति में होने के नाते खुश ही होता, लेकिन हमें उस खुशी से भी वंचित किया गया। महिलाओं के अधिकारों की बात करें, तो यहां पर 200 मीटर दूर ही हमारी

---

* Expunged as ordered by the Chair.

महिला, जो ओलम्पिक विनर हैं और हाल ही में उन्होंने एक पदक जीता है, वे प्रोटेस्ट कर रही थीं। वे आपसे मांग कर रही थीं कि प्रधान मंत्री जी, जब हम पदक जीते हैं, तो आपने हमारा साथ दिया है और जब हम आपसे कुछ मांग कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा साथ दीजिए। कहीं न कहीं उनकी सुनवाई नहीं की गई। अभी भी जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया है, वे ही ऐसी बॉडीज़ पर खड़े हैं या influence कर रहे हैं, जो दुखदायी है। Crimes against women के बारे में फौजिया जी ने बाकायदा बताया कि किस तरीके से इसके आंकड़े बढ़े हैं, तो मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगी। Farmers' suicides के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। किसानों की बात की गई - अन्नदाता। अन्नदाता की सुसाइड को लेकर प्रति दिन जितने केसेज़ सामने आते हैं, यह मेरा डेटा नहीं है और अगर आप कहेंगे, तो मैं स्पष्टीकरण भी दे दूंगी। ...(**समय की घंटी**)... सर, बस मैं कन्क्लूड ही कर रही हूं। हर रोज 30 किसान आत्महत्या करते हैं। आमदनी दोगुनी करने की बात भी की गई थी, दोगुनी तो दूर की बात है, जबकि वे जान की बाजी लगाते हैं और खेती करते हैं। हमने जो farmer distress देखा, rural distress देखा...

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः I think राष्ट्रपति जी कह रही थीं कि महिलाओं का workforce participation भी बढ़ा है, वह rural distress के कारण बढ़ा है। यही देश का दुर्भाग्य है कि आज इनकी सरकार 10 साल रही और वही चार नारे फिर से गूंज रहे हैं, जिन चार नारों को पूरा करने का काम 2014 में प्रधान मंत्री नरेन्द्र ने किया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच समाप्त करती हूं। Thank you so much.

MR. CHAIRMAN: I think there are some issues on which we need to be really very rational. The epochal development about women reservation was supported by the entire Parliament. And enlightened Members of Parliament, you being one of them, Priyankaji know that a process has to go through, and before you really get fruition of it, there will have to be identification of constituencies. All of us know it. It has to generate an ecosystem. You say that something has been given but those at the door are not being given. Whenever it was to be given by any dispensation, any Parliament, some time would have to be taken. Therefore, let us not emanate an impression that something has been given which could be immediately implemented. You know that delimitation is required. You know that identification has to take place. It was done with the participation of everyone. For three decades, our mothers and sisters were waiting to get this reservation. Ultimately, with the cooperation of all and the lead of the Executive, this has fructified. This is a celebratory occasion. And on this celebratory occasion, you give an impression like this that something has just been given on paper. Have it from me in my capacity as the Chairman that it is a constitutional prescription. It is embedded in our Constitution. This is a constitutional

right - one-third women's reservation in the Lok Sabha and State Legislatures. It is vertical and horizontal. Therefore, there will have to be necessary processes. I leave it at that.

Shri Nabam Rebia. Ten Minutes. ...(*Interruptions*)... No. You are a very enlightened Member.

SHRI NABAM REBIA (Arunachal Pradesh): Thank you, Sir, for having given me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address which the hon. President of India has been pleased to deliver. The Motion has been moved by sister Smt. Kavita Patidar and seconded by Shri Vivek Thakur. I will not be harping on all those issues which have been mentioned by many other Members of this hon. House regarding the achievements and various schemes benefiting various sections of the country, especially the focus on *gareeb, mahilaayein, yuva* and *anna data*. North-East has been repeatedly mentioned by many speakers which I don't want to repeat. मैं कहता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ, तो आज अपने आप को भारतीय कहने में बहुत गर्व महसूस करता हूँ। It is because of Narendra Modi's policies. नॉर्थ-ईस्ट के बारे में मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, किसी ने सोचा नहीं था कि this could be possible. Abrogation of Article 370, ट्रिपल तलाक किसी ने सोचा नहीं था। अभी वीमेन रिजर्वेशन आ गया, राम मंदिर बन गया। देखिए, what an achievement for the country. मोदी जी देश को pinnacle of glory and success में ले जा रहे हैं। Rightly, he is taking the country to the status of Vishwa Guru, from toilet to the Moon and beyond that. I think we should accept and agree on the good things that he is doing. Hopefully, in another five-ten years, Modi *ji* will change the face of India. He has already changed it. And he will change it further and India will emerge as a superpower.

Now I will come to the North-East. Many speakers have mentioned about the problems in the North-East. Look at the initiative taken by the Modi Government. In the Council of Ministers, two Cabinet Ministers are from the North-East Region. There are a number of Ministers of State. Earlier, we had hardly one Cabinet Minister. It could be possibly from Assam. During the Congress regime, मेघालय से मि. पी.आर. कींडिया हुआ करते थे, बाकी MoS at the most. अभी देखिए, this is the concern. Earlier it was 'Look East Policy'; now, under Modi, it is 'Act East Policy'. The intention is there. आप मोदी जी की नीयत को देखिए। Kindly bear with me. पहले नॉर्थ-ईस्ट के मंत्री या चीफ मिनिस्टर किसी मंत्री से मिलने के लिए यहाँ दिल्ली में आते थे, तो यहाँ सप्ताह भर या महीना भर बैठना पड़ता था। उनको appointment ही नहीं मिलता था। अभी तो बिन बुलाये सारे मंत्री वहाँ आ रहे हैं। Ministers are coming. It is 'Government at the door'. प्राइम मिनिस्टर हर telephone call को attend करते हैं। What more do you want? वहाँ infrastructure development कितना हो रहा है! मणिपुर में जो happening हो रही है, we know that Modiji

will be able to find a solution to Manipur also. सर, नॉर्थ-ईस्ट के लोगों में पहले एक isolation syndrome था। That isolation syndrome has gone. Earlier, we thought that we are not in the mainstream of the nation. That was our feeling. अभी क्या है - कुछ नहीं है। We are Indians. अभी हमारे लोगों का जो main concern है, growing generation, young generation का जो एक concern है, it is the change of demographic pattern. वहाँ demographic pattern न बदल जाए। I am from Arunachal Pradesh; I should not be outnumbered or reduced to minority. That was the feeling. वहाँ demographic pattern नहीं बदलना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा डर यह है। इसके ऊपर भारत सरकार काम कर रही है। We are happy. Secondly, हमारे एरिया में inter-State boundary dispute हुआ करता था, वह अभी भी है, लेकिन मोदी सरकार personally, with our Home Minister, Amit Shahji, is taking initiative. वहाँ जितनी inter-State boundary problems हैं, सीमा-समस्या को solve करने के लिए सरकार जो काम कर रही है, we do welcome it and hopefully, in a very short time, हमारे नॉर्थ-ईस्ट की सीमा-समस्या भी सोल्व होनी है। यह हमारा विश्वास है। In the President's Address, it is mentioned that there is reduction in incidents of separatism. Not only separatism, secessionist elements were also there. आप देखिए कि पहले नॉर्थ-ईस्ट में हर समय एक 'बन्द' होता था। If there is a *bandh* in Guwahati, लोग कहते थे कि नॉर्थ-ईस्ट में 'बन्द' हो रहा है। नॉर्थ-ईस्ट सिर्फ गुवाहाटी नहीं है, सिर्फ असम नहीं है। Including Sikkim, we have eight States. असम में कुछ होता था, तो सब लोग कहते थे कि वहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ बन्द हो रहा है। वहाँ अब ऐसा नहीं है। वहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब हर स्टेट में एयरपोर्ट्स बन गए हैं। आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। मोदी जी के आने के बाद we have four airports today. वहाँ trains हैं, regular trains हैं, rail lines हैं, rail heads हैं, शताब्दी ट्रेन है। दिल्ली से वहाँ ट्रेन जाती है, गुवाहाटी से शताब्दी ट्रेन चलती है। What more we want? लोग सोचते हैं, they are surprised what is happening in India. यह क्या हो रहा है! लेकिन गाँव के लोग केवल मोदी जी का नाम जानते हैं। वहाँ पहले क्या हुआ करता था, अभी क्या हो रहा है! वहाँ सब कुछ मिल रहा है। Sir, this is the change we see in our North-East Region.

सर, यहाँ मैं गवर्नमेंट को एक बात और भी बताना चाहूँगा। There were Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873 and Chin Hills Regulation of 1896. These statutes were made by the Britishers. But they are relevant even today to protect the interests of the tribal and indigenous people of the region. इस प्रोविजन को नहीं हटाना चाहिए। हमारे यहाँ स्टेट में अभी तक inner line system चलता है। These two regulations should not be done away with. It should be allowed to continue. एक और है, वह यह है कि the former Governor of Assam and Jammu & Kashmir, General S.K. Sinha, I believe, if I am not wrong, made a report. You can have access to that also. There, he has said, there seems to be a design to carve out a Bengali-speaking Muslim country in the North East. He has cautioned us, he has cautioned the Government of India. I think, day

before yesterday or the day before, some hon. Member mentioned about the 'Chicken's neck'. यही है। The Central Government should take note of it.

MR. CHAIRMAN: One minute, please. Hon. Members, the House was scheduled to meet up to 7.30 p.m. The time is extended up to 8.30 p.m. Please continue.

SHRI NABAM REBIA: So, it was General Sinha's report. I have talked about Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873 and Chin Hills Regulation of 1896 for the information of the hon. Members and the Government. अभी वहाँ पर Vibrant Village Programme चल रहा है। हमारा अरुणाचल प्रदेश geographically नॉर्थ-ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर पहाड़ ज्यादा हैं, फिर भी यह सबसे बड़ा राज्य है। यह जो Vibrant Village Programme है.....

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI NABAM REBIA: Sir, I am concluding. इस Vibrant Village Programme से लोगों की सोच-विचार में बहुत बदलाव हो रहा है। People now have started going back to the interiors. हम अपनी पुरानी जगह पर जा रहे हैं।

Lastly, to conclude, I am taking the opportunity of my speech. पहले से ही अरुणाचल प्रदेश सरकार और हमने भी इस सदन में बहुत बार इस मुद्दे को रखा है कि Arunachal Pradesh should be included in the Sixth Schedule of the Constitution of India and Article 371H has to be strengthened because Arunachal Pradesh has purely 100 per cent tribal population.

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...*(Interruptions)*...

SHRI NABAM REBIA: The special constitutional guarantee, which has been given to the State of Mizoram and Nagaland, has not been given to Arunachal Pradesh. Thank you, Sir, for having given me this chance.

MR. CHAIRMAN: Shri Ramji, five minutes.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका और साथ ही अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के क्रियाकलापों, योजनाओं और लक्ष्य को ध्यान में रख कर दिया गया संबोधन होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा, 'अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने

पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं', जब कि सच्चाई कुछ और है। आज गरीब आदमी शिक्षा और नौकरी से महरूम कर दिया गया, जिसका मुख्य कारण शिक्षा का बाजारीकरण है। इसकी वजह से गरीब और गरीब हुआ। आज गरीब आदमी को 5 किलो राशन देने मात्र से गरीबी दूर होने वाली नहीं है। इस सरकार ने भी पिछली काँग्रेस सरकार की ही तरह पिछले 10 सालों में गरीबी को लेकर खोखले वादे ही किए। मान्यवर, इसकी वजह से इस बात की पुष्टि भी होती है कि सरकार 10 सालों में अवाम को इतना मजबूत नहीं कर पाई कि वह 5 किलो राशन खरीद सके।

मान्यवर, अर्थव्यवस्था के बारे में तमाम बड़ी-बड़ी बातें की गईं। आज डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया, अफगानिस्तान के अफगानी रुपए से भी पीछे है। इसके साथ ही किसानों के लिए कहा गया कि किसान एमएसपी पा रहा है, फसल बीमा मिल रहा है। यदि सब मिल रहा है, तो पिछले साल 11,290 भारतीय किसानों ने आत्महत्या क्यों की? यह एक छोटा-मोटा आँकड़ा नहीं है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि भारतीय किसान के हालात ठीक नहीं हैं।

मान्यवर, बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े पाँच स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया गया, यह एक सराहनीय कदम है। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन में वंचित-दलित समाज के उत्थान को लेकर कुछ नहीं कहा गया, जबकि आज भी दलित समाज और आदिवासी समाज पर अत्याचार रोकने में सरकार नाकाम साबित हुई है। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में देश में लगभग 53,886 मामले एससी-एसटी पर अत्याचार को लेकर दर्ज हुए। यही नहीं, एक घटना बिहार की है कि वहां की सरकार ने किस तरह से एक दलित आई.ए.एस., श्री जी. कृष्णैय्या के हत्यारे को छोड़ने का काम किया, यह पूरा देश जानता है। मान्यवर, इस अभिभाषण में महिलाओं के संबंध में भी तमाम तरह की बातें बताई गईं। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन सालों में एनसीआरबी के अनुसार देश में 13 लाख महिलाएं लापता हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, देश में लगभग 80 से 90 बलात्कार रोज होते हैं। मान्यवर, एससी-एसटी के बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार कोई खास कदम नहीं उठा रही है। एससी-एसटी के बच्चे देश की मुख्य धारा से पीछे जा रहे हैं। उनके फ्री एडमिशन की व्यवस्था खत्म कर दी गई और छात्रवृत्ति को भी लगभग खत्म कर दिया गया।

मान्यवर, बाबा साहेब का सपना देश को विकसित राष्ट्र बनाने का था और उसके लिए बाबा साहेब ने बहुत सुंदर और बड़ा महान संविधान इस देश को दिया, जिसमें विकसित भारत को लेकर तमाम तरह की संभावनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन मात्र हर जगह विकसित-विकसित कहने पर ही भारत विकसित नहीं हो सकता है, बल्कि इसके लिए सोच भी विकसित करनी होगी, बाबा साहेब के संविधान की मंशा के अनुरूप चलना पड़ेगा। संविधान जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, equality की बात करता है और fraternity की बात करता है। वंचितों और पीड़ितों को जब तक सामाजिक न्याय नहीं दिया जाएगा, तब तक विकसित भारत की बात अधूरी है। जब तक इन कमजोर वर्गों को हर क्षेत्र में समानता का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक विकसित भारत की बात अधूरी है, इसलिए सरकार एससी-एसटी वर्ग के लोगों के लिए कम से कम प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करे, ताकि यह वर्ग भी देश की मुख्य धारा में आ सके।

मान्यवर, अब मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कर्तव्य पथ पर लगाए जाने की जानकारी दी गई, साहबजादों की याद में 'वीर बाल दिवस' और भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित किया गया, जो कि एक सराहनीय

कदम है। अगर बेजुबानों की आवाज़, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों के हक एवं हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले बहुजन नायक माननीय श्री कांशीराम साहब जी के जन्म दिवस को भी राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दिवस घोषित किया जाता तो एक बड़ा संदेश वंचित वर्ग को भी जाता, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत!

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Jebi Mather Hisham; two minutes.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, I wish to draw the attention of this House on the need for introduction of separate pay scale and other service benefits to ASHA workers. ASHA workers who are the backbone of rural health infrastructure have been tirelessly striving to bridge the gap between the communities and the healthcare system. 'A Million Champions of Health and Hope', is how our hon. Health Minister had described them when they were honoured with Global Health Leaders Award by the WHO in May, 2022. However, their crucial role is often undervalued with meagre remuneration, lack of benefits and challenging work conditions. Their work is conveniently brought under the umbrella of societal or voluntary service and are paid with scanty honorariums and incentives.

MR. CHAIRMAN: Your contribution on President's Address; thank you.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: Sir, ASHA workers are currently paid fixed honorariums, often amounting to just Rs. 6,000 per month. This is highly inadequate as far as their extensive workload and responsibilities are concerned. There is no social security and lack of EPF, healthcare and pensions...

MR. CHAIRMAN: Thank you. ...*(Time-Bell rings.)*...

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM: In this context, I urge upon the Central Government to appoint a high-level Commission to study the factual position and implement the same.

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. Sumer Singh Solanki; ten minutes.

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, नर्मदे हर!

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही मेरी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों, राज्य सभा और लोक सभा के समक्ष भव्य, दिव्य एवं ऐतिहासिक नए संसद भवन में, जहां सभ्यता और संस्कृति की चेतना है, उसी भवन में दिनांक 31 जनवरी, 2024 को अभिभाषण दिया है, इसके लिए मैं माननीया राष्ट्रपति जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आज से 10 वर्ष पहले के भारत और आज के भारत में फ़र्क या अंतर साफ नज़र आता है। आज का भारत माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में शक्तिशाली भारत, नेतृत्व करने वाला भारत, सहयोग करने वाला भारत और विश्व को परिवार मानने वाला भारत - गरीब, युवा, महिला और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाला भारत बनकर उभरा है। महोदय, आज यह दुनिया को रास्ता दिखाने वाला और विश्वास देने वाला भारत है। आज हमारे भारत के अंदर देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुं ओर विकास की गंगा बह रही है, इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, युवा, किसान और महिला के जीवन को बेहतर बनाकर ज़िन्दगी बदलने का कार्य किया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस देश में 60 साल तक इस वर्ग की कभी चिंता नहीं की, इनका सिर्फ वोट बैंक के रूप में शोषण किया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से अरुणाचल प्रदेश तक, लक्षद्वीप हो या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, संपूर्ण भारतवर्ष की हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा गरीब परिवारों की ज़िन्दगी बदलने का और ज़िन्दगी संवारने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय यह भी रहा है कि उन्होंने गरीबों की ज़िन्दगी बदलने के लिए, गरीब भाईयों और बहनों का कल्याण करने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किया है और आज हमारे देश के करोड़ों भाइयों और बहनों की ज़िन्दगी हमेशा के लिए खुशनुमा हो गई है। माननीय सभापति महोदय, इस देश के अंदर दूरस्थ और आदिवासी इलाकों में कभी कच्चे झोपड़े हुआ करते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे। बारिश के दिनों में हवा, आंधी और तूफान में वे उड़ जाया करते थे, लेकिन कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी पक्का मकान देने का उनका सपना पूरा नहीं किया। जब ज़रूरत पड़ती थी, तब उस झोपड़ी के सामने कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जाकर फोटो खिंचवाते थे और उस फोटो को अखबारों में छपवाते थे, गरीब होने का ढोंग करते थे, लेकिन उन्होंने गरीबी दूर करने का कभी प्रयास नहीं किया। देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने पहली बार इस देश के अंदर 4 करोड़ 10 लाख गरीब भाइयों और बहनों को पक्के मकान बना कर देने का काम किया है। मैं कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि एक बार आप जाइए और माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी द्वारा जो घर बनाया गया है, उसके सामने भी एक सेल्फी लेकर कम से कम शेयर या पोस्ट तो कर दीजिए, ताकि पता चले कि आपके ज़माने में क्या था और हमारे मोदी जी की सरकार में क्या हुआ है। महोदय, गरीब भाइयों और बहनों को 13 करोड़ गैस कनेक्शन दिये गये, 11 करोड़ परिवार जनों को 'जल जीवन मिशन' के तहत नल से जल देने का काम किया गया, 10 जनजाति संग्रहालयों का निर्माण किया गया, 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के तहत पौने चार लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया, 53 करोड़

'आयुष्मान भारत योजना' के कार्ड का निर्माण किया गया, जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर आदिवासी भाइयों और बहनों को गौरवान्वित करने का काम किया गया, धारा 370 को हटाकर जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों और बहनों को आरक्षण देने का काम किया गया। तमाम ऐसे काम देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किये हैं, जिनसे सबसे ज्यादा अगर कोई लाभान्वित हुआ है, तो वह मेरा आदिवासी समाज हुआ है, मेरा गरीब समाज हुआ है, मेरा अनुसूचित जाति का समाज हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, आज इन गरीब भाइयों और बहनों की ज़िन्दगी बदलने के लिए 10 करोड़ किसान भाइयों और बहनों को 'किसान सम्मान निधि' का लाभ दिया जा रहा है। गरीब और छोटे जिले, जो पिछड़े हुए जनजातीय और पहाड़ी जिले हैं, उन जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में चिह्नित करके वहां भी विकास की गंगा बहाने का काम अगर किसी ने किया है, तो हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। माननीय सभापति महोदय, एक ज़माना था, जब भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के विकास की गंगा कभी पूर्ववर्ती सरकारों में महलों की तरफ बहा करती थी, लेकिन जब देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, तब यह विकास की गंगा गरीबों की झोपड़ियों का कायाकल्प करने के लिए गांवों की ओर अंतिम छोर तक बह रही है, यह देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने करके दिखाया है। 'पीएम-जनमन योजना', 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना', 'जन धन योजना', 740 एकलव्य विद्यालय, 14,000 से अधिक पीएम श्री स्कूल, वनाधिकार कानून, सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के साथ-साथ शिक्षा नीति में परिवर्तन करके हमारे गरीब भाई और बहनें, जो अंग्रेजी में एमबीबीएस या मेडिकल या अन्य पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उनका स्थानीय भाषा और हिन्दी भाषा में अनुवाद करके हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा अगर इस देश के अंदर पहली बार हुई है, तो देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे मध्य प्रदेश में हुई है। मैं आज यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों के लिए मध्य प्रदेश के अंदर संत रविदास के 100 करोड़ के मंदिर का भूमि पूजन भी देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। इस प्रकार मोदी जी के श्रेष्ठ नेतृत्व में मेरी सरकार देश में 140 करोड़ भाइयों और बहनों के सपनों को पूरा करने की गारंटी देती है और यही गारंटी आपके 60 वर्षों की पुरानी गारंटी या फर्जी गारंटी को खत्म करती है। हमारी सरकार जो कहती है, वही करती है। यही मोदी जी की गारंटी है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एससी/एसटी भाइयों के कल्याणार्थ अनेक महत्वपूर्ण विधेयक भी संसद में प्रस्तुत कर कानून का रूप देने के लिए सराहनीय कार्य किए हैं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्री राम सनातन काल से ही आदिवासी भाइयों की आस्था और विश्वास के केंद्र बिंदु रहे हैं। हर कार्य में राम नाम लिए बिना कोई काम नहीं होता है - यह आदिवासी समाज की परंपरा रही है। ये हमारी जनजातीय परंपरा का वाहक रहे हैं। आज उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और जब रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई...(**समय की घंटी**)... तो देश के लगभग 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा समय अभी बचा हुआ है। मुझे दस मिनट का समय दिया गया है। मैं एक लाइन कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं ने कभी खुलकर तारीफ नहीं की और कभी

धन्यवाद भी नहीं दिया। जिस भवन में ये बैठे हुए हैं, उसी भवन का लोकार्पण जब किया गया, तो कांग्रेसियों ने कभी मोदी जी को धन्यवाद नहीं दिया। चार करोड़ के पक्के मकान बने, उसके लिए मोदी जी को कांग्रेस और विपक्ष ने कभी धन्यवाद नहीं दिया। 53 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने, उसके लिए कांग्रेस ने मोदी जी को कभी धन्यवाद नहीं दिया। इस देश के अंदर समस्त प्रकार की योजनाओं को लागू करके जनजाति समाज का कल्याण करने का काम किया, लेकिन मोदी जी को कांग्रेस या विपक्ष ने कभी धन्यवाद नहीं दिया। माननीय सभापति जी, मैं एक लाइन बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं माननीय मोदी जी के लिए विपक्ष को सुनाने के लिए बोल रहा हूं-

"रेत पर नाम हम लिखते नहीं,
क्योंकि रेत पर नाम टिकते नहीं,
पत्थर दिल हैं यारों हम तो,
जो नाम सीने पर लिखते हैं,
वे कभी मिटते नहीं।"

इस भारत का गौरव, इस भारत का इतिहास बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर जारी रहेगा। यही कहते हुए जय हिन्द, जय भारत, नर्मदे: हर!

MR. CHAIRMAN: Those of the Members who wish to lay their Special Mentions on the Table of the House, may do so. Now, Shri Aneel Prasad Hegde. You are known to be very brief and very sharp.

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE (Bihar): Yes, Sir. I will conclude within my time.

Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity. I rise to speak in support of the President's Address. First of all, I thank the Prime Minister for conferring Bharat Ratna to Jan Nayak Karpoori Thakur*ji* and Lal Krishna Advani*ji*. My Party JDU, led by Shri Nitish Kumar and founded by socialist followers like George Fernandes is a democratic socialist party fighting for strengthening democracy, secularism, removal of manmade inequalities and against violation of human rights. मेरा दल गैर-बराबरी मिटाने के लिए काम करता है। चाहे वह अमीर-गरीब के बीच का हो, पुरुष-महिला के बीच का हो, जाति-जाति के बीच का हो या शहर-ग्रामीण और प्रदेश के बीच का हो। इसी दिशा में चलकर नवंबर 2005 में मुख्य मंत्री बनते ही नीतीश कुमार ने पंचायती राज और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया और गैर-बराबरी मिटाने के क्रम में बिहार देश में पहला राज्य बना। जातिगत जनगणना कराकर भी सामाजिक न्याय की दिशा में बिहार पहला राज्य बना। 'हर घर नल से जल' कार्यक्रम लागू करके शहर की सुविधा गांवों में भी पहुंचाई। यहां कल शराबबंदी के बारे में जिक्र हुआ है। मुख्य रूप से घरेलू हिंसा से महिलाओं को राहत देने के लिए गांधी जी की अति प्रिय और अति कठिन शराबबंदी को नीतीश कुमार सरकार ने आठ साल से लागू रखा है। मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि संसद और असेम्बली में

उन्होंने महिला आरक्षण दिया, जल-जीवन मिशन लागू किया और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कई सारी चीज़ें हैं, जो मेरे जीवन से, मेरे काम से जुड़ी हैं, तो मैं मेरे अनुभव से बोलूंगा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बताया गया है कि खादी की बिक्री चार गुणा बढ़ी है। प्रधान मंत्री जी ने अक्टूबर माह में अपने "मन की बात" कार्यक्रम में हाथ से बनी वस्तुओं को खरीदने का निवेदन किया है। मैंने हर सैशन में लगातार खादी के बारे में प्रश्न पूछा है और मुझे हमेशा संतोषजनक जबाव मिला है। मैं उससे संतुष्ट हूं। मैं 1984 में राजनीति में आया था। उस समय असम, पंजाब, कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट में अलगाववाद, विद्रोह, बगावत चरम पर था। भोपाल गैस त्रासदी भी उसी साल हुई थी। पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जो कि नीरज शेखर जी के पिता जी हैं, वे मेरी पार्टी के अध्यक्ष थे। वे भोंडसी के सेंटर में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर कराते थे। उस समय मासूम कार्यकर्ता लोग भोलेपन से बोलते थे कि पाकिस्तान से, विदेश से पैसा लेकर कश्मीर में, पूर्वोत्तर में अलगाववाद हो रहा है। उस समय मेरी पार्टी के नेता लोग बोलते थे कि unemployment is the mother of all evils, and idle mind is a devil's workshop. कोई व्यक्ति, कोई खास धर्म में पैदा होने से गलत काम नहीं करता है, बल्कि बेरोजगारी ही सारी बीमारी की जड़ है। इसलिए रोजगार सृजन के लिए हमें काम करना चाहिए। वे आगे कहते थे कि Industrial Policy Document of the 1977 Morarji Desai Government is the Gita for us. उस समय जॉर्ज फर्नांडिस इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, अटल जी और आडवाणी जी उसी सरकार में मंत्री थे। लोग बिहार और यू.पी. से हजारों किलोमीटर दूर रोजगार की तलाश में मुम्बई शहर जाते थे और वे धारावी की झुग्गी-झोपड़ी में नारकीय जीवन बिताते थे। ...(**समय की घंटी**)... मजदूरों का पलायन न हो, इसलिए 300 जिलों में जिला उद्योग केंद्र बनाये गए थे। प्रशिक्षण शिविर में हम लोगों को मिल के कपड़े में और हैंडलूम के कपड़े में फर्क बताते थे। मिल मेड में सूत भी मिल का होता है और कपड़ा भी मिल का होता है, लेकिन हैंडलूम में सूत तो मिल का होता है, लेकिन बुनकर उसी सूत से कपड़े की बुनाई करता है, बुनकर द्वारा हाथ से कताई किया हुआ, सूत से बुनकर द्वारा बुनाई किया हुआ कपड़ा अगर लोग पहनेंगे, तो 50 गुणा ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। यह बात मेरे मन में बैठ गई कि बुनकरों के द्वारा बुना हुआ कपड़ा पहनने से रोजगार का सृजन होगा, इसीलिए मैं करीब 38 साल से खादी के अलावा और कोई कपड़ा नहीं पहनता हूं। मैं सिर्फ खादी का कपड़ा खरीदता और पहनता हूं। यहां तक कि मैं पिछले 38 साल से हाथ से बना हुआ जूता पहनता हूं। नागपुर के Cotton Research Centre में 40 साल से वैज्ञानिक डॉ. केशव क्रांति अपने अनुभव से बताते हैं कि 1790 में ब्रिटिश ने भारत में Egyptian cotton बीज लगाने की कोशिश की। इस कपास के बीज को...

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE: Sir, I have seventeen minutes. Sir, 9th is the last day when I will enter this Chamber, please. I will finish my speech within that, please. इस कपास की staple length उनका Manchester and Lancashire Mill को सूट करता है। भारत से निकलते वक्त 1947 तक वे सिर्फ तीन प्रतिशत ही कपास के बीज लगवा पाए और 97 परसेंट कपास के बीज बचे हुए थे, लेकिन 2002 में चोरी से BT Cotton का बीज आया। Mahyco

Monsanto Company ने अपने patent किये हुए BT Cotton का खूब प्रचार किया कि ज्यादा फसल होगी और उसके लिए कीटनाशक pesticide की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि भारी मात्रा में pesticide और पानी की जरूरत है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

श्री अनिल प्रसाद हेगडे : सर, 2011 आते-आते पता चला कि यील्ड में देशी बीज और BT Cotton में फर्क नहीं है। देश में अब BT Cotton का बीज है और उसकी monopoly हो चुकी है, सिर्फ 2 प्रतिशत देशी बीज बचा है। मैंने महाराष्ट्र के नांदेड़ में जाकर, वहां के कॉटन रिसर्च सेंटर में से जो डेढ़ क्विंटल देशी बीज बचा था, उसमें से 81 किलो बीज खरीदकर देश में अलग-अलग प्रदेश के किसानों को multiply करने के लिए दिया है। मैं सिर्फ देशी कपास से कत्तिन द्वारा कताई किया हुआ, सूत से बुनकर द्वारा बुनाई किया हुआ कपड़ा ही पहनता हूं।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE: Sir, I will finish within the time. I have told you, Sir, that after 9th, I will not enter the Chamber.

MR. CHAIRMAN: You have one minute.

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE: No, Sir, I have to make a conclusion also; oherwise, whatever I have said will all go meaningless.

सर, विदेशी कम्पनियों के द्वारा बीज के पेटेंट करने के खतरे को ध्यान में रखते हुए समाजवादी लोग, गांधीवादी लोग और संघ परिवार के स्वदेशी जागरण मंच को साथ लेकर WTO में हस्ताक्षर के खिलाफ जॉर्ज फर्नांडिस ने एक एग्रेसिव केम्पैन 90 के दशक में शुरू किया था। इसी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में 1994 से लेकर 2008 तक, हर रोज 14 साल तक, 5,120 दिनों तक कार्यकर्ता गिरफ्तारी देते थे। इसमें मैंने भी नज़दीक से 4 हज़ार बार भाग लिया है। मेरे 15 दिन तिहाड़ जेल में बीते, उस समय लेफ्ट पार्टीज़ भी GATT/WTO का विरोध करती थीं। हम बेरोज़गारी मिटाने की बात करते हैं, दलित, ओबीसी को न्याय दिलाने के बारे में बोलते हैं, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण, दलित एवं आदिवासियों के सशक्तिकरण के बारे में बोलते हैं, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बोलते हैं, गाँधी जी का नाम लेते हैं, कत्तिन बुनकर में अधिकांश लोग महिला, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं। हम उनका बनाया हुआ पर्यावरण स्नेही सामान नहीं खरीदते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि अक्टूबर के 'मन की बात' कार्यक्रम में उन्होंने बोला है कि आप जिस भी प्रदेश में जाते हैं, अपना 10 प्रतिशत बजट वहाँ की स्थानीय वस्तु को खरीदने में लगा लीजिए। दिल्ली में मेरे घर पर चार लोग कताई करते हैं और सिखाते भी हैं। मैं मेरे घर के सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग और किचन गार्डनिंग करता हूं, हर्बल प्लांट लगाता हूं, देशी बीज बचाने वाले अभियान से जुड़ा हूं, मैं सीड सेवर रहा हूं

और मैंने 134 किस्म के धान की वैरायटी लगाई है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, जो बहुत रेलेवेंट है और मेरी बात का कंक्लूज़न भी इसी से आएगा कि देश के 50 लाख बीड़ी मजदूरों के लिए जो योजनाएं हैं, हाउसिंग स्कीम्स आदि, जिनमें 40 हज़ार रुपये मिलते थे, अब उनमें 1 लाख रुपये बढ़ गए हैं। आपको इसी संबंध में जानकारी देना चाहता हूं कि मैं बिहार के 38 जिलों में गया हूं, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में गया हूं, महाराष्ट्र का सोलापुर, जहाँ बीड़ी मजदूरों के लिए 10 हज़ार मकान बने हैं, मैं इन लोगों के नेता, सीपीएम से पूर्व विधायक श्री आदम मास्टर से उसी कॉलोनी में मिला हूं।

सर, अंसारी सरनेम के लोग बुनकर होते हैं। इसमें अधिकांश लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं। जब हैंडलूम की डिमांड कम हुई, तो उसका बुरा असर भी हुआ है, क्योंकि बीड़ी मजदूरों में अधिकांश महिलाएं हैं। मोहम्मद शमीम अंसारी बीड़ी वर्कर के बारे में एक स्टडी है, the work of beedi making is primarily carried out by workers having socio-economic status like Scheduled Castes and Muslim OBCs who lost their traditional source of livelihood in weaving etc. due to cheap industrial substitutes and changing consumer preference. अलग-अलग प्रदेश में हज़ार बीड़ी बनाने के लिए 24 रुपये से लेकर 40 रुपये तक मिलते थे। मेरी पार्टी के संविधान के अनुसार जहाँ सक्रिय सदस्य बनने के लिए हाथ से कताई किया हुआ, सूत से बुनाई किया हुआ खादी का कपड़ा पहनना जरूरी है, वहीं कांग्रेस के संविधान में एक कदम आगे लिखा है कि सदस्य बनने के लिए सर्टिफाइड खादी पहनना जरूरी है। खरगे साहब सत्ता में लेबर मिनिस्टर थे, मैंने 2011 में इस संबंध में कई सारी आरटीआईज़ में जवाब भी प्राप्त किया है।

सर, अब मैं अपना कंक्लूज़न देता हूं कि एक तरफ प्रधान मंत्री जी चरखे के पीछे बैठकर खादी बिक्री के लिए खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर प्रचार कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने यह आया है कि खादी की बिक्री चार गुना बढ़ी है। जहाँ प्रधान मंत्री जी महिलाओं, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलित, आदिवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं यह भी देख रहा हूं कि बुनकरों को बीड़ी मजदूर बनाने में सबसे ज्यादा योगदान रखने वाली पार्टी का कोई राजकुमार अपने खानदान की गलती का प्रायश्चित करने के लिए, जिनकी अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार सर्टिफाइड खादी पहननी चाहिए..(**व्यवधान**)..

MR. CHAIRMAN: Please conclude now, Shri Hegde.

श्री अनिल प्रसाद हेगडे: वह मिल का कपड़ा, टी शर्ट पहनकर घूम रहा है, यात्रा कर रहा है, बीड़ी मजदूर से मिलकर सेल्फी खिंचवा रहा है। मेरी पार्टी के नेता के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, वह चुटकुला सुना रहा है। ..(**व्यवधान**)..

MR. CHAIRMAN: Shri Hegde, you are reading. *(Time-bell rings)*

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE: I am finishing, Sir. *(Time-bell rings)*

MR. CHAIRMAN: You are reading all throughout.

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE: No, no; I will just finish in time. If you give me time, I will speak extempore.

MR. CHAIRMAN: No, no; you are hundred per cent reading out from a document. This is not allowed.

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE: Sir, you give me half a minute. I will make one point and conclude.

MR. CHAIRMAN: I will give you 30 seconds.

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE: Finally, it will be 25 years on February 15th, when the leader of the 4.5 crore Kurdish people, Abdullah Ocalan had been incarcerated in Turkish jail. I appeal to the Government through the hon. External Affairs Minister to intervene with Mr. Erdogan of Turkey to get him released early. Earlier, India had extended solidarity with Nelson Mandela, Dalai Lama and Aung San Suu Kyi.

MR. CHAIRMAN: Shri Hegde, always be very cautious when Dr. John Brittas appreciates. Trust me, you will be the gainer. If he appreciates you too much, you have lost your way. He is appreciating.

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE: Let me complete, Sir.

MR. CHAIRMAN: No, don't look there. Look at me. Your time is over. I will give you the last 20 seconds. You have the last twenty seconds.

8.00 **P.M.**

श्री अनिल प्रसाद हेगडे: मैं देवेगौड़ा साहब को बधाई देता हूँ कि उनके प्रधान मंत्री रहते हुए, जब उनकी ही पार्टी के मुख्य मंत्री चारा घोटाले में लिप्त थे, उन्हें उन्होंने नहीं बचाया। उनकी जगह पर गुजराल साहब आए, वे चाहकर भी मुख्य मंत्री को बचा नहीं पाए। इसके बारे में तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर ने लिखा है। सबसे पहले जो मुख्य मंत्री चारा घोटाले में जेल गए, वे अपनी ही पार्टी के प्रधान मंत्री रहते हुए जेल गए थे।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Mr. Hegde.

श्री अनिल प्रसाद हेगडे : Vindictive के बारे में बताया जाता है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have already indicated that there are 16 permitted Special Mentions for today. As all the Members concerned are not present, I suggest that the Special Mentions of those hon. Members who are present may be deemed to have been laid on the Table of the House.

---

*SPECIAL MENTIONS

Demand to grant compensatory attempts to UPSC aspirants suffered during Covid-19 pandemic

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Sir, I seek justice for countless sincere UPSC Civil Services Examination (CSE) candidates who faced immense difficulties during the COVID-19 pandemic.

Granting compensatory attempts in the UPSC CSE exam as a one-time relief measure would fulfil the genuine aspirations of lakhs of candidates unable to prepare adequately amidst unprecedented challenges.

Many UPSC aspirants saw their lives disrupted by the COVID-19 pandemic from 2020-2022. Candidates and their families were affected, with loss of lives and prevention from attempting the exam. Trauma during the CSE exams in 2020-22 was widespread, with candidates forced into quarantine, depriving them of the opportunity to attempt the UPSC exam.

DoPT and UPSC have historically compensated candidates for adversities, like in 2014 and 2015. Mistakes in the UPSC CSE Prelims 2022 resulted in elimination of many deserving candidates, indicating a precedent for compensatory attempts.

The Parliament Standing Committee on DoPT has also recommended a compensatory attempt and relief for aspirants in its 112th Report.

Sir, 18 States and Union Territories, including Bihar, Uttar Pradesh and Maharashtra, compensated for pandemic-related disruptions in exams from 2020-2023. Also, the Union Government extended similar COVID relief to candidates in various exams, like SSC-GD and MBBS.

---

* Laid on the Table